

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अग्रिम जमानत संख्या- 7842/2023

.....

राजकुमारी

.....अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ, प्रवर्तन निदेशालय, रांची

.....प्रतिवादी

साथ ही

अग्रिम जमानत संख्या- 7821/2023

.....

गेंदा राम

.....अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ, प्रवर्तन निदेशालय, रांची

.....प्रतिवादी

.....

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से

: श्री जितेन्द्र एस. सिंह, अधिवक्ता

: श्री शुभाशीष रासिक सोरेन, अधिवक्ता

: श्रीमती शोभा ग्लोरिया लकड़ा, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष की ओर से

: श्री प्रशांत विद्यार्थी, वरिष्ठ पी.सी., भारत संघ

सुनवाई पूर्ण: 22.03.2024

निर्णय घोषित: 12.04.2024

चूंकि ये दोनों आवेदन एक ही सामान्य ईसीआईआर से संबंधित हैं, इसलिए पक्षकारों की सहमति से इन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा निस्तारित किया जाता है ।

प्रार्थना

1. यह याचिकाएँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत दायर की गई हैं, जिसमें अग्रिम जमानत की प्रार्थना की गई है, ईसीआईआर मामले संख्या 2/2023 में, जो कि ईसीआईआर-आरएनजेडओ/16/2020 दिनांक 17.09.2020 के तहत पंजीकृत है। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए और धारा 4 के तहत दंडनीय है, जो वर्तमान में रांची में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-VIII-सह-विशेष न्यायाधीश, पीएमएल अधिनियम, की अदालत में लंबित है।

अभियोजन पक्ष का मामला

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि एसीबी, जमशेदपुर द्वारा पंजीकृत एफआईआर संख्या 13/2019 दिनांक-13.11.2019 से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ईसीआईआर/आरएनएसजेडओ/16/2020 दिनांक-17.09.2020 दर्ज करके धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की गई थी ।

3. इसके बाद जांच एजेंसी द्वारा धारा 120-बी और 201 आईपीसी और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 (बी) के तहत आरोपी व्यक्तियों अर्थात् आलोक रंजन और सुरेश प्रसाद वर्मा के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दिनांक- 11.01.2020 को दायर की गई है ।
4. इसके अलावा, धारा 17 पीएमएल अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों और उनके करीबी सहयोगियों की भूमिका की जांच करने के लिए विभिन्न स्थानों पर वर्तमान मामले के संबंध में की गई तलाशी कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि अपराध की आय का एक हिस्सा आरोपी वीरेंद्र कुमार राम, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा निविदाओं के आवंटन के बदले कमीशन/रिश्वत के रूप में प्राप्त किया गया था। उक्त रिश्वत का पैसा दिल्ली स्थित सीए मुकेश मित्तल के कर्मचारियों/रिश्तेदारों के बैंक खातों की मदद से वीरेंद्र कुमार राम के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भेजा जा रहा था। यह भी पता बता है कि वीरेंद्र कुमार राम अन्य प्रविष्टि प्रदाता बैंक में प्रविष्टियां लेते थे अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के खाते और फिर ऐसे फंड मुकेश मित्तल द्वारा बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था सह अभियुक्त राजकुमारी (वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी) और गेंदा राम (वीरेंद्र कुमार राम के पिता)। दोनों यहां याचिकाकर्ताओं ।
5. यह भी पता चला है कि वीरेंद्र कुमार राम मुकेश मित्तल को नकद राशि देता था, जो उसकी मदद से अन्य प्रविष्टि प्रदाता अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में प्रविष्टियाँ लेते थे और फिर मुकेश मित्तल द्वारा इस तरह के फंड को सह-आरोपी राजकुमारी (वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी) और गेंदा राम (वीरेंद्र कुमार राम के पिता) के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था। दोनों ही यहाँ याचिकाकर्ता हैं ।
6. इसके अलावा, यह भी पता चला है कि कुछ बैंक जाली दस्तावेजों के आधार पर (दिल्ली में) खोले गए खातों का भी धन की इस तरह की रूटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए, धन की इस तरह की रूटिंग से संबंधित निष्कर्षों को आई.ओ. द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया गया था।

इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा (i) वीरेंद्र कुमार राम, (ii) मुकेश मित्तल और (iii) अज्ञात अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं 419, 420, 465, 466, 468, 471, 473, 474, 476, 484 और 120-बी, और निर्दिष्ट बैंक नोट्स (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम; 2017 की धारा 7 और 5 के तहत एक एफआईआर संख्या 22/2023 दर्ज की गई थी ।

7. अभियोजन पक्ष की शिकायत से पता चलता है कि 21.02.2023 को की गई तलाशी के दौरान विभिन्न रिकॉर्ड, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, नकदी, आभूषण, वाहन बरामद किए गए और जब्त किए गए और जांच के दौरान उन्हें अपराध की आय से एकत्र किया गया पाया गया ।
8. तदनुसार, अभियोजन पक्ष ने मामले में अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की है और उस संज्ञान के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 और धारा 4 के तहत अपराध के लिए 29.04.2023 को कार्रवाई की गई है ।
9. याचिकाकर्ता/अभियुक्त राजकुमारी के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि उसने जानबूझकर अपने पति, जो सह-अभियुक्त है, को उसके नाम पर नई दिल्ली में अचल संपत्ति खरीदने में सहायता की और खरीद पर विचार का भुगतान उसके पति द्वारा किए गए अपराध की आय से किया गया था। वीरेंद्र कुमार राम ।
10. याचिकाकर्ता/अभियुक्त गेंदा राम के खिलाफ विशेष आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे वीरेंद्र कुमार राम, जो सह-अभियुक्त है, को अपने नाम पर आयोग से 22.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदने में मदद की। रिश्त की रकम, जो उनके बेटे वीरेंद्र कुमार राम ने हासिल की थी. इसके अलावा, उक्त याचिकाकर्ता के बैंक खाते के विवरण में 4.525 करोड़ रुपये का भारी क्रेडिट दर्शाया गया है ।

11. तदनुसार, कथित अपराध के संबंध में, वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका संख्या को प्राथमिकता दी थी। 2023 का 1551 और 2023 का 1549 गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने के लिए था, लेकिन अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-XVIII-सह-विशेष न्यायाधीश, पीएमएल अधिनियम, रांची की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2023 द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था ।

12. इसलिए वर्तमान आवेदन दायर किए गए हैं ।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया तर्क:

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जितेंद्र एस. सिंह ने अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर तर्क दिया है:

- I. याचिकाकर्ता बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के लिए परोक्ष उद्देश्य और गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है ।
- II. ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिससे पीएमएल अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित किया जा सके क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धन शोधन का कोई आरोप नहीं है ।
- III. वैकल्पिक रूप से, प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया जाता है, तब भी यह पीएमएल अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध नहीं होगा, क्योंकि आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आवश्यक सामग्री से कम हैं ।
- IV. प्रवर्तन निदेशालय ने वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में दोषी ठहराने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, जबकि उन्हें विधेय अपराध से दूर-दूर तक नहीं जोड़ा जा सकता है, जो वर्तमान मामले में एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 13/2019 दिनांक 13.11.2019 है ।

- V. एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 13/2019 दिनांक 13.11.2019 बिछाए गए जाल के बाद दर्ज की गई थी श्री सुरेश प्रसाद वर्मा के खिलाफ और उपरोक्त एफआईआर में कार्रवाई के उक्त कारण से उत्पन्न जांच शामिल है। इसलिए, एफआईआर संख्या 13/2019 दिनांक 13.11.2019 याचिकाकर्ता के पति से कथित रूप से जुड़े कार्रवाई के कारण से उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का वर्तमान ईसीआईआर के विधेय अपराध से कोई कथित संबंध भी नहीं है ।
- VI. याचिकाकर्ता धन शोधन में संलिप्त नहीं हैं क्योंकि उन्होंने आयकर विभाग को अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है, जो रिकार्ड से स्पष्ट है ।
- VII. यह स्थापित धारणा है कि वित्तीय लेन-देन करने वाला/करने वाला व्यक्ति शुरू में यह नहीं जान सकता कि वित्तीय लेन-देन में शामिल धन अपराध की आय है और याचिकाकर्ता उस अभियुक्त की पत्नी और पिता हैं, इसलिए, यह स्वतः यह अनुमान नहीं लगाता कि उस अभियुक्त द्वारा दिया गया धन अपराध की आय है। हालाँकि, वर्तमान मामले में वीरेंद्र कुमार राम (अभियुक्त संख्या 1) और याचिकाकर्ता स्वयं भी पूर्वगामी अपराध में अभियुक्त नहीं हैं ।
- VIII. धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्तें याचिकाकर्ता राजकुमारी पर लागू नहीं होतीं क्योंकि वह एक महिला हैं और धारा 45 पीएमएलए की शर्त के अंतर्गत आती हैं । पीएमएलए की धारा 45(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक अधिदेश को आगे बढ़ाती प्रतीत होती है जो महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाती है ।
- IX. उपर्युक्त संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा देवकी नंदन मामले में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है । गर्ग बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2022) 6 एचसीसी (डी.एल.) 67 में यह तर्क दिया गया है

कि धारा 45(1) का परन्तुक सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, महिला, अथवा बीमार या अशक्त व्यक्तियों के लिए छूट के रूप में शामिल किया गया है ।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधारों पर तर्क दिया है कि मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से, ऊपर उल्लिखित आधारों के अनुसार, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी पूर्व जमानत के विशेषाधिकार का लाभ दिया जाना चाहिए ।

विपक्षी पक्ष-प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क:

15. दूसरी ओर, विपक्षी प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार दास ने उपरोक्त तथ्य और कानून के आधार पर उक्त प्रस्तुति/आधार का गंभीरता से विरोध किया है ।

1. जहां तक बाद की एफआईआर का संबंध है, यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लेना गलत है कि चूंकि पहली एफआईआर 13.11.2019 की है और उसके बाद यह पाया गया कि पैसा दिल्ली में भेजा जा रहा था, तब दूसरी एफआईआर 03.03.2023 को दर्ज की गई। इसलिए, कोई अवैधता नहीं है क्योंकि शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार पहली एफआईआर आलोक रंजन के खिलाफ है, जिन्होंने सह-आरोपी वीरेंद्र कुमार राम द्वारा अवैध रूप से दिए जा रहे धन के संरक्षक होने की सूचना दी है। जबकि दूसरी एफआईआर एफआईआर नंबर 22/2023 उक्त वीरेंद्र कुमार राम द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए उक्त धन के रूटिंग की जांच के लिए है। फिर ऐसी परिस्थितियों में, शिकायत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई है ।

- II. इसके अलावा, वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की गई जांच के दौरान सामने आए आरोपों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धन शोधन में याचिकाकर्ताओं की प्रत्यक्ष संलिप्तता पाई गई है ।
- III. प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान अधिवक्ता ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप का उल्लेख किया है । याचिकाकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी वीरेंद्र कुमार राम 48,94,10,877 रुपये की अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और छिपाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से और सीधे तौर पर शामिल था और उसने अपनी पत्नी राजकुमारी के बैंक खाते में 9.3 करोड़ रुपये और अपने पिता गेंदा राम के बैंक खाते में 4.535 रुपये की फर्जी प्रविष्टियां कीं और इस राशि का उपयोग वाहन, अन्य संपत्ति खरीदने के लिए किया गया और एक शानदार जीवन जी रहे हैं ।
- IV. प्रतिवादी-ईडी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि सह-आरोपी तारा चंद और हरीश यादव की नियमित जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा क्रमशः बी.ए. संख्या 11095/2023 और बी.ए. संख्या 9734/2023 में पारित दिनांक 01.03.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है और सह-आरोपी मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका भी इस न्यायालय द्वारा ए.बी.ए. संख्या 10671/2023 में पारित दिनांक 16.02.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है, जिसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए और पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता को लागू किया गया है।
- V. याचिकाकर्ता अपराध की आय पर कब्जा करने, उसे छिपाने और उपयोग करने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं और जानबूझकर इसमें सहायता भी की है । वीरेंद्र कुमार राम (अभियुक्त नंबर 1) ने इसे बेदाग के रूप में पेश किया,

इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने पीएमएल अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है ।

- VI. पीएमएलए के प्रावधान एक स्वतंत्र अपराध हैं क्योंकि पीएमएलए एक अलग विशेष कानून है। पीएमएलए, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच एक अनुसूचित अपराध करने के बाद शुरू की जाती है, जिसमें से आय उत्पन्न की गई है। जांच के दौरान, अपराध की आय के भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग में याचिकाकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सामने आई है ।
- VII. इसके अलावा जांच के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों के दौरान कभी भी अपनी आय के वास्तविक स्रोत का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं अर्थात् राजकुमारी ने केवल फॉर्म नंबर बीए की एक प्रति जमा की है। आयकर विभाग द्वारा उन्हें जो नोटिस जारी किए गए थे। हालाँकि, उक्त याचिका में, उन्होंने शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश के साथ-साथ आभूषण, सोना और चांदी बुलियन और व्यापार में निवेश में उपयोग किए गए धन/आय के स्रोत का खुलासा नहीं किया है । जिसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि उक्त क्रेडिट आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे ।
- VIII. इसके अलावा, ऊपर उठाए गए तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल आय की घोषणा करना और स्रोत प्रदान किए बिना कर का भुगतान करना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से मुक्त नहीं होता है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता का पति भारी भ्रष्टाचार में शामिल है, जो याचिकाकर्ता या परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित सभी संपत्तियों का आधार है ।
- IX. याचिकाकर्ता राजकुमारी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि उनके बैंक खातों में प्राप्त सभी

धनराशि का स्रोत पति वीरेंद्र कुमार राम द्वारा बताया जाएगा, और वीरेंद्र कुमार राम ने अपने बयान में बताया है। पीएमएलए की धारा 50 में कहा गया है कि उपरोक्त क्रेडिट नकदी के बदले उक्त खातों में प्राप्त प्रविष्टियों में से हैं, जिसका स्रोत वीरेंद्र कुमार राम द्वारा प्राप्त कमीशन था, जिसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि उक्त क्रेडिट नकदी के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। आपराधिक गतिविधियों का कमीशन ।

- X. इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावों में कोई दम नहीं है और ये दस्तावेजी हैं याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि या प्रमाण के लिए साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए जाएं ।
- XI. इसके अलावा प्रतिवादी के विद्वान वकील ने रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 11 एससीसी 46 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता है, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध की आय शामिल नहीं है, याचिकाकर्ता पर है ।
- XII. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि धारा 45 के प्रावधान केवल आवेदक के महिला होने के कारण वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकते, पूरी तरह से गलत है। प्रतिवादी ईडी के विद्वान वकील ने शिवानी राजीव सक्सेना बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। दिनांक 15.09.2017 को जमानत आवेदन 1518/2017 में आदेश दिया गया था, जिसमें आरोपी, जो एक महिला थी, को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि अदालत ने

देखा कि विवेक के आवेदन में वर्णित है। धारा 45(1) के प्रावधान को एक मानक नियम के रूप में सार्वभौमिक रूप से लागू करने के बजाय व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों के आसपास की अनूठी परिस्थितियों पर विचार करते हुए लागू किया जाना चाहिए कि उक्त प्रावधान में उन सभी श्रेणियों के लोगों को जमानत दी जानी चाहिए।

XIII. इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 437(1) के साथ एक सादृश्य बनाते हुए। और जमानत याचिका में मीनू दीवान बनाम राज्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया जा रहा है। संख्या 736/2008 जिसमें यह माना गया कि ऐसा कोई पूर्ण या बिना शर्त नियम नहीं है कि यदि आरोपी महिला है तो जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन अपराध की प्रकृति और गंभीरता और ऐसे अपराध की जघन्यता पर भी विचार करना होगा और उसी तरह परिस्थिति-दर-परिस्थिति भिन्न होती है।

XIV. यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के दौरान और संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 में गिरफ्तार नहीं होने पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की जमानत पर विचार करने से पहले आरोपों की गंभीरता पर विचार किया जाएगा।

16. उपरोक्त आधारों के आधार पर प्रतिवादी-प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपराध की आय को सीधे प्राप्त करने में उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जाए।

पार्टियों की ओर से की गई दलीलों का विश्लेषण:

17. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दलीलों के साथ-साथ विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को भी देखा है ।
18. यह न्यायालय, पक्षों की ओर से दिए गए तर्क की सराहना करने से पहले, अधिनियम, 2002 के तहत निहित कानून के कुछ प्रावधानों पर इसके उद्देश्य और इरादे के साथ चर्चा करना उचित और उचित समझता है ।
19. यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने, अपराध की आय की कुर्की, न्यायनिर्णयन और उसे केंद्र सरकार में निहित करने सहित जब्त करने, एजेंसियों और तंत्र की स्थापना के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए उपायों का समन्वय करना और अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना ।
20. नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में इन मुद्दों पर गहन बहस की गई, सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य 1989 में घोषित, 14 से 16 जुलाई, 1989 को पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में FATF की स्थापना, 23.2.1990 के अपने संकल्प संख्या S-17/2 के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और कार्रवाई का महान कार्यक्रम, 8 से 10 जून, 1998 को विश्व ड्रग समस्या का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में राज्य दलों से एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह किया गया। यह विधेयक के साथ प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट है जो 2002 का अधिनियम बन गया । वही इस प्रकार पढ़ता है:

"परिचय

मनी-लॉन्ड्रिंग न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ऐसे खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि मनी-लॉन्ड्रिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम विधेयक, 1998 पेश किया गया था। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।

वस्तुओं और कारणों का विवरण

दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि मनी-लॉन्ड्रिंग न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए, बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई कुछ पहलों की रूपरेखा नीचे दी गई है:-

(ए) नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसमें भारत एक पार्टी है, नशीली दवाओं के अपराधों और अन्य संबंधित गतिविधियों की आय के शोधन को रोकने और ऐसे अपराध से प्राप्त आय को जब्त करने का आह्वान करता है।

(बी) 1989 में प्रतिपादित सिद्धांतों के बेसल वक्तव्य में उन बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है जिनका बैंकों को मनी-लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए पालन करना चाहिए।

(सी) मनी-लॉन्ड्रिंग की समस्या की जांच के लिए 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ने चालीस सिफारिशों की हैं, जो व्यापक कानून के लिए आधार सामग्री प्रदान करती हैं। मनी-लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए सिफारिशों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख हैं-

(i) गंभीर अपराधों के माध्यम से किए गए धन के शोधन को आपराधिक अपराध घोषित करना;

(ii) रिपोर्ट योग्य लेनदेन के संबंध में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रकटीकरण के तौर-तरीकों पर काम करना;

(iii) अपराध की आय को जब्त करना;

(iv) मनी-लॉन्ड्रिंग को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना; और

(v) मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(डी) 23 फरवरी, 1990 के संकल्प संख्या एस-17/2 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और कार्रवाई का वैश्विक कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य राज्यों से वित्तीय संस्थानों को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने का आह्वान करता है। नशीली दवाओं से संबंधित धन के शोधन और ऐसे शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

(ई) संयुक्त राष्ट्र ने 8 से 10 जून, 1998 को विश्व नशीली दवाओं की समस्या का एक साथ मुकाबला करने पर विशेष सत्र में धन-शोधन से निपटने की आवश्यकता के संबंध में एक और घोषणा की है। भारत इस घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है।

21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम 2002 को अन्य बातों के साथ-साथ मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने, अपराध की आय की कुर्की, मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन

और जल्दी और मुकदमा चलाने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता का उत्तर देने के लिए अधिनियमित किया गया था। अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्ति।

22. इसमें अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत प्रदान की गई "अपराध की आय" की परिभाषा को संदर्भित करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है:

"2(यू) "अपराध की आय" का अर्थ किसी अनुसूचित अपराध या मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति है किसी ऐसी संपत्ति का या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई हो या रखी गई हो, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के समतुल्य मूल्य;

[स्पष्टीकरण: संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त हो सकती है:]"

23. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "अपराध की आय" से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य से है।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित

किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई हो।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण को अधिनियम 23/2019 के माध्यम से कानून की पुस्तक में शामिल किया गया है।

24. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 2(1)(यू) के तहत स्पष्टीकरण देने का कारण यह है कि क्या धारा 2(1)(यू) के मूल प्रावधान के अनुसार, संपत्ति सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई है। अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप या किसी ऐसी संपत्ति के मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई हो, लेकिन स्पष्टीकरण के तौर पर अपराध की आय को व्यापक निहितार्थ दिया गया है, जिसमें न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त हो सकती है।

25. धारा 2(1)(v) के अंतर्गत "संपत्ति" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है हर प्रकार की कोई भी संपत्ति या परिसंपत्ति, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त तथा इसमें ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों पर हक या हित को प्रमाणित करने वाले कार्य और उपकरण शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों।

26. अनुसूची को धारा 2(1)(x) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची से है। "अनुसूचित अपराध" को धारा 2(1)(y) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2(य) "अनुसूचित अपराध" से तात्पर्य है -

(i) अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; या

(ii) अनुसूची के भाग बी के तहत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपये] या उससे अधिक है; या

(iii) अनुसूची के भाग सी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध ।”

27. "अनुसूचित अपराध" के अर्थ से स्पष्ट है कि अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; अनुसूची के भाग बी के तहत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपये] या अधिक है; या अनुसूची के भाग सी के तहत निर्दिष्ट अपराध ।

28. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

"3. मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध- जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें उसका छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा ।

[स्पष्टीकरण। स्पष्ट किया कि,- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह कहा गया है

(i) कोई व्यक्ति मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल है अपराध की आय के साथ,
अर्थात्:-

(ए) छिपाना; या

(बी) कब्जा; या

(सी) अधिग्रहण; या

(डी) उपयोग; या

(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या

(एफ) किसी भी तरीके से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना;

(ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छुपाकर या कब्जे में लेकर या अधिग्रहण या उपयोग करके आनंद नहीं ले रहा हो या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या किसी भी तरीके से इसे बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना।]"

29. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध" का अर्थ है जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा ।

30. यह और भी स्पष्ट है कि अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छुपाने या कब्जे में लेने या अधिग्रहण या उपयोग करने या उसे बेदाग के रूप में पेश करके आनंद ले रहा हो। संपत्ति या किसी भी तरीके से इसे बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना ।

31. मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा का प्रावधान अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत किया गया है ।

32. अधिनियम, 2002 की धारा 50 अधिकारियों को समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने के संबंध में शक्ति प्रदान करती है। त्वरित संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2002 की धारा 50 इस प्रकार है:

"50. सम्मन, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियाँ-

(1) निदेशक को धारा 13 के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसमें रिपोर्टिंग इकाई का कोई अधिकारी भी शामिल है, उपस्थिति के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ग) अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(घ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ई) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सके ।

(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझे, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए ।

(3) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, जैसा अधिकारी निर्देश दे, स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे और जिस विषय के संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही हो, उस पर सत्य कथन करने या कथन करने तथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे ।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उसके समक्ष पेश किए गए किसी अभिलेख को, जितनी वह ठीक समझे, परिबद्ध कर सकेगा तथा उसे अपनी अभिरक्षा में ऐसी अवधि के लिए रख सकेगा, जितनी वह ठीक समझे:

बशर्ते कि सहायक निदेशक या उप निदेशक-

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को रिकार्ड किए बिना किसी अभिलेख को जब्त कर लेगा; या

(ख) संयुक्त निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, ऐसे किसी भी अभिलेख को तीन माह से अधिक अवधि तक अपने पास नहीं रखेगा ।"

33. अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ "अपराध की आय" की परिभाषा की व्याख्या पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929 के मामले में विचार किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और मंशा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला किया है। अनुच्छेद-251 के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा ।

34. उस शर्त की व्याख्या, जिसे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पूरा किया जाना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूर्वनिर्धारित अपराध में शामिल है, पैराग्राफ-265 से स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। आसान संदर्भ के लिए, पैराग्राफ को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है: प्रासंगिक

"265. दूसरे शब्दों में कहें तो, 2019 से पहले की धारा में "सहित" शब्द शामिल था, जो अपराध की आय से जुड़ी विभिन्न प्रक्रिया या गतिविधि के लिए किए गए संदर्भ का संकेत है। इस प्रकार, मुख्य प्रावधान (जैसा कि स्पष्टीकरण भी) यह भविष्यवाणी करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उसे धन शोधन के अपराध का दोषी माना जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित व्याख्या को स्वीकार किया जाना था, तो यह अनुसरण करेगा कि यह केवल प्रश्नगत संपत्ति को पेश करने या दावा करने पर ही है बेदाग संपत्ति, अपराध पूर्ण होगा। यह अधिनियम की धारा 3 के पीछे विधायी मंशा की प्रभावशीलता को कमजोर करेगा और साथ ही FATF द्वारा "प्रक्षेपण या दावा" अभिव्यक्ति से पहले "और" शब्द की घटना के संबंध में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की अवहेलना करेगा। प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अनुबंध और अभिसमय यद्यपि नगरपालिका कानून का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन न्यायालयों द्वारा उन्हें संदर्भित किया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उक्त संधियों का एक पक्ष है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान और अन्य चल रहे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पढ़ा गया है। यह भी देखा गया है कि भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमय को ध्यान में रखते हुए आवश्यक रूप से समझा जाना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान विश्व समुदाय की संस्थाओं का ध्यान रखता है जिन्हें बनाया गया था। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए.के. चोपड़ा के मामले में न्यायालय ने कहा कि घरेलू न्यायालयों का दायित्व है कि वे घरेलू कानूनों की व्याख्या करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय

सम्मेलनों और मानदंडों को उचित सम्मान दें, खासकर तब, जब उनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून में कोई कमी हो। इस दृष्टिकोण को गीता हरिहरन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ में भी दोहराया गया है।”

35. धारा 50 के निहितार्थ को भी ध्यान में रखा गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-422, 424, 425, 431, 434 इस प्रकार हैं:

"422. इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है। क्योंकि, यह 2002 अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान दर्ज करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि व्यक्ति को सही और सटीक जानकारी का खुलासा करना चाहिए। जांच की विषय वस्तु के संबंध में उनकी व्यक्तिगत जानकारी में ज्ञात तथ्य। व्यक्ति 2002 अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में मिथ्या या गलत होने के लिए दंडित किए जाने की धमकी के साथ दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य है। इससे पहले कि हम मामले का आगे विश्लेषण करें, संशोधित 2002 अधिनियम की धारा 50 को पुनः प्रस्तुत करना उचित है।

424. इस प्रावधान के द्वारा, निदेशक को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जो 1908 संहिता के तहत एक सिविल न्यायालय में निहित हैं। यह 2002 अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में है, जो बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों द्वारा कमीशन और चूक के कृत्यों के संबंध में जुर्माना लगाने की निदेशक की शक्तियों से संबंधित है। जिस सेटिंग में धारा 50 रखी गई है और धारा 13 के तहत जुर्माना लगाने के प्रयोजनों के लिए सिविल कोर्ट में निहित शक्तियों के

साथ निदेशक को सशक्त बनाने का विस्तार, स्पष्ट रूप से बहुत विशिष्ट है और अन्यथा नहीं।

425. वास्तव में, धारा 50 की उपधारा (2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम बनाती है, जिसकी उपस्थिति वह साक्ष्य देने या पाठ्यक्रम के दौरान कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक समझती है। इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही की। हमने पहले ही इस फैसले के पहले भाग में अभिव्यक्ति "कार्यवाही" की चौड़ाई पर प्रकाश डाला है और माना है कि यह निर्णय प्राधिकारी या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है, जैसा भी मामला हो। फिर भी, उपधारा (2) अधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है। हम यह समझने में विफल हैं कि ऐसे समन के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 20(3) कैसे लागू होगा, जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। वास्तव में, जिस व्यक्ति को इस प्रकार बुलाया गया है, वह व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य है, जिसके संबंध में उसकी जांच की जा रही है या उससे बयान देने और दस्तावेज पेश करने की उम्मीद की जाती है। अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के आधार पर आवश्यक हो सकता है। आलोचना अनिवार्य रूप से उपधारा (4) के कारण है जो यह प्रावधान करती है कि उपधारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही को आईपीसी की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20(3) या उस मामले के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, केवल तभी लागू होगी जब बुलाया गया व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी अपराध का

आरोपी हो और उसे अपराध करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। अपने ही विरुद्ध गवाही देना। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। इस न्यायालय की संविधान पीठ म.प्र. शर्मा ने इसी तरह की एक चुनौती का सामना किया था जिसमें जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हुए वारंट जारी किए गए थे। इस न्यायालय ने राय दी कि अनुच्छेद 20(3) में गारंटी "प्रशंसापत्र बाध्यता" के विरुद्ध है और मौखिक साक्ष्य तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, यह तब शुरू हो जाता है जब व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो केवल मौखिक साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करने के कारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, गवाह होना साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा और कुछ नहीं है और ऐसे साक्ष्य विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"मोटे तौर पर कहा गया है कि अनुच्छेद 20(3) में गारंटी "प्रशंसापत्र बाध्यता" के विरुद्ध है। यह सुझाव दिया गया है कि यह किसी अपराध के मुकदमे में खड़े व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य तक ही सीमित है, जब उसे गवाह के रूप में बुलाया जाता है। हम ऐसा नहीं देख सकते हैं संवैधानिक गारंटी की सामग्री को इस बमुश्किल शाब्दिक आयात तक सीमित करने का कारण इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की गारंटी को लूटना होगा और जैसा कि कुछ अमेरिकी निर्णयों में कहा गया है, ध्वनि के सार को खोना होगा (3) "साक्षी बनना" है। एक व्यक्ति न केवल मौखिक साक्ष्य देकर, बल्कि दस्तावेज प्रस्तुत करके या समझने योग्य इशारे करके भी "साक्षी बन सकता है" (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें)।) या इस तरह "गवाह बनना" "प्रस्तुत करना" से अधिक कुछ नहीं है साक्ष्य" और ऐसा साक्ष्य मुंह से या किसी चीज या दस्तावेज के उत्पादन या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां तक

दस्तावेजों के उत्पादन का सवाल है, निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि सम्मन पर दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं है। लेकिन उस धारा का उद्देश्य जिरह के अधिकार को विनियमित करना है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके प्राकृतिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, यानी, साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करना। वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, गवाही है, और साक्ष्य संबंधी बाध्यता जबरदस्ती को दर्शाती है जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य कृत्यों को प्राप्त करती है, जो उसकी ओर से चुप्पी या समर्पण के नकारात्मक रवैये के विपरीत है। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल अदालत कक्ष में परीक्षण के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह होना" है न कि "साक्षी के रूप में प्रकट होना" गवाह"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा, जहाँ तक यह "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित है, केवल न्यायालय कक्ष में गवाही देने के लिए बाध्यता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्यतापूर्ण गवाही तक भी विस्तारित हो सकती है। इसलिए यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है, जिसके विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से अभियोजन हो सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।"

(जोर दिया गया)

431. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि धारा 50 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपराध की आय के बारे में जांच के संबंध में समन जारी किया जाता है, जिसे कुर्क किया जा सकता है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष

न्यायनिर्णयन लंबित है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी मामले की सुनवाई शुरू की जाए। नोटिस प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अभियोजन। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, यद्यपि वास्तविक अर्थ में जांच के रूप में है, अपराध की आय के संबंध में कार्यवाही आरंभ करने या उसे आगे बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि स्थिति ऐसा करने की मांग करती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अलग बात है कि जांच के दौरान एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध के किए जाने और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए समन के अनुसरण में प्रकटीकरण करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं। इस स्तर पर, धन शोधन के अपराध के आरोपी के रूप में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से धन शोधन के अपराध या अपराध की आय के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति के अपराध की आय होने के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए जांच नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और सबूतों के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके

किए गए या न किए गए कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम यह आग्रह करने के लिए लागू हो सकते हैं कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। उसके दावे की मिथ्याता को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।

434. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों में निवेश की गई शक्ति अपराध की आय के अस्तित्व और उससे जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्तियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए है ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके। ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती, कुर्की और जब्ती भी शामिल है जो अंततः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

36. ऊपर दिए गए अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 2002 अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, धन-शोधन के अपराध के लिए सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि धन की रोकथाम के लिए उपाय भी प्रदान करता है- लॉन्ड्रिंग। यह अपराध की आय की कुर्की के लिए भी प्रावधान करता है, जिसे छुपाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या किसी भी तरीके से निपटाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 2002 अधिनियम के तहत ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही में निराशा हो सकती है। यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने, 2002 अधिनियम के अध्याय

IV के संदर्भ में निर्धारित समय के भीतर ऐसे लेनदेन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए भी है।

37. पूर्वोक्त निर्णय में विधेय अपराध पर विचार किया गया है, जिसमें 2019 के अधिनियम 23 के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा के तहत शामिल किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा गया है। धारा 2(1)(यू), जिसके द्वारा तथा जिसके अंतर्गत संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि, "अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि, "कोई भी संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है" अपराध की आय के अंतर्गत आएगी।

38. जहां तक धारा 45(1)(i)(ii) के तात्पर्य का संबंध है, उपरोक्त प्रावधान गैर-बाधित खंड से शुरू होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

उपधारा (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने पर सीमाओं के अतिरिक्त सीमाएं लगाती है। जमानत देने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण यह भी है कि उप-धारा (2) के तहत, जो संदेहों को दूर करने के प्रयोजन के लिए है, एक स्पष्टीकरण डाला गया है कि "संज्ञेय और अजमानतीय अपराधों का होना" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसका हमेशा यही अर्थ समझा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और अजमानतीय अपराध होंगे, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इसके विपरीत कोई बात निहित हो, और तदनुसार इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं।

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के पैराग्राफ 371-374 में धारा 45 के निहितार्थ की व्याख्या की गई है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त पैराग्राफ को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

"371. 2002 अधिनियम में जमानत के बारे में प्रासंगिक प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित अध्याय VII में धारा 44 (2), 45 और 46 में पाए जा सकते हैं। मुख्य शिकायत 2002 अधिनियम की धारा 45 में निर्दिष्ट दोहरी शर्तों के बारे में है। इससे पहले कि हम आगे विस्तार से बताएं, संशोधित धारा 45 को फिर से प्रस्तुत करना उचित होगा। यह इस प्रकार है:

"45. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।-(1) [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या महिला है, या बीमार या अशक्त है, या तो अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर एक करोड़ रुपये से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोपी है, उसे जेल भेजा जा सकता है।

यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे तो जमानत पर रिहा किया जा सकता है:

आगे यह भी प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि वह लिखित रूप में निम्नलिखित द्वारा की गई शिकायत पर न हो-

(i) निदेशक; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उस सरकार द्वारा किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।

(1क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न कर दिया जाए।)

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत मंजूर करने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सीमाओं के अतिरिक्त है।

[स्पष्टीकरण. शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराधों का होना" पद का अभिप्राय यह है और सदैव यही समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय अपराध तथा अजमानतीय अपराध होंगे, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कोई प्रतिकूल बात क्यों न हो, और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी धारा 19 के अधीन शर्तों को पूरा करने तथा इस धारा के अधीन प्रतिष्ठापित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं।]"

372. धारा 45 को 2005 के अधिनियम 20, 2018 के अधिनियम 13 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के द्वारा संशोधित किया गया है। 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पढ़े गए। धारा 45 की उपधारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि वह तब थी, निकेश ताराचंद शाह में विचार की गई थी। इस न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) को, जैसा कि वह तब थी, जमानत पर रिहाई के लिए दो और शर्तें लगाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया। जिन दो शर्तों का उल्लेख जुड़वां शर्तों के रूप में किया गया है, वे हैं:

- (i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; तथा
- (ii) जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

373. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा दोनों शर्तों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसलिए वे समाप्त हो गई हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए मणिपुर राज्य के कथन पर भरोसा किया गया है।

374. हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है कि क्या कानून में, दोहरी शर्तें, कानून में बनी रहीं निकेश ताराचंद शाह मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद की पुस्तक और यदि हाँ, तो 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) में अधिनियम 13/2018 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई महत्व नहीं होगा। इस तर्क को हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर राज्य के मामले में फैसले के पैराग्राफ 29 में यह टिप्पणी प्रासंगिक है कि न्यायालय द्वारा यह घोषित कर देने के कारण कि कानून असंवैधानिक है, कानून पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जैसे कि इसे कभी पारित ही नहीं किया गया था। इस मामले में, न्यायालय निरसन अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने निरसन अधिनियम पर ध्यान दिया और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त टिप्पणी की। तर्क की प्रक्रिया में, इसने बेहराम खुर्शीद पेसिकका और दीप चंद में की गई व्याख्या पर ध्यान दिया, जिसमें क्ली ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशन और नॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी में अमेरिकी न्यायशास्त्र की व्याख्या शामिल है।"

40. इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1486 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है कि चूंकि धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं, इसलिए उनका अनुपालन किया जाना

चाहिए। न्यायालय को यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

यह भी देखा गया है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह मानने का हकदार है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में 3, अपराध की ऐसी आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का पालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर पीएमएल अधिनियम को दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-17 इस प्रकार है:

"17. जैसा कि अब तक तय हो चुका है, धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है कि अभियुक्त के इस तरह के अपराध का दोषी न होने और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना न होने के बारे में विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण को यह मानने का अधिकार है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में

उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि पीएमएल अधिनियम को पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए।"

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे यह निर्धारित किया है कि जमानत का लाभ देने से पहले अधिनियम, 2002 की धारा 45 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोहरी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) में विचार किया है। जिसमें यह पाया गया कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) में दिए गए निर्णय में, इसके पैराग्राफ-284 के अंतर्गत, यह माना गया है कि 2002 अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए तभी मुकदमा चलाना चाहिए, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास "अपराध की आय" है। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाता है, जो अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता को दर्शाता है, तो अधिनियम के तहत अपराध की आय की कुर्की और जब्ती के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है और जब तक कि यह केंद्र सरकार में निहित नहीं हो जाती, तब तक शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी।

जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत देने के मुद्दे का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विजय मदनलाल चौधरी और अन्य

बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) में दिए गए फैसले के पैराग्राफ-412 में यह टिप्पणी करते हुए माना गया है कि राहत चाहे किसी भी रूप में दी गई हो, जिसमें कार्यवाही की प्रकृति भी शामिल है, चाहे वह धारा 438 के तहत हो 1973 की संहिता की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरताओं को लागू किया जाना चाहिए और बिना किसी अपवाद के 2002 अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए विचार किया जाना चाहिए, जो कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है।

43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार के मामले में मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, (2015) 16 एससीसी 1 के माध्यम से पैराग्राफ-30 में यह माना है कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 में यह आवश्यक है कि सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे, जब तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं और धारा 71 में यह प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का किसी अन्य कानून में निहित असंगतता के बावजूद अधिभावी प्रभाव होगा। पीएमएलए का अधिभावी प्रभाव होता है और सीआरपीसी के प्रावधान तभी लागू होंगे, जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हों। इसलिए, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन निम्नलिखित के संबंध में भी करना होगा धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए आवेदन किया गया। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, प्राधिकारी या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार उस पर है कि अपराध की आय शामिल नहीं है। अपीलकर्ता त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-30 इस प्रकार है:

"30 पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन करने की आवश्यकता है, जिसे धारा 65 के प्रावधानों और पीएमएलए की धारा 71 द्वारा और भी मजबूत किया गया है। धारा 65 के लिए आवश्यक है कि सीआरपीसी के प्रावधान उसी हद तक लागू होंगे जहां तक वे हैं इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और धारा 71 में प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में असंगत कुछ भी होने के बावजूद अधिभावी प्रभाव होगा और सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे केवल अगर वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, तो धारा 439 सीआरपीसी के तहत किए गए जमानत के आवेदन के संबंध में भी पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा धारा 24 में प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, प्राधिकारी या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध की आय शामिल नहीं है।"

44. अब वर्तमान मामले और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार कहा जा रहा है कि इसे सामग्री को आकर्षित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है पीएमएलए 2022 की धारा 3 जबकि दूसरी ओर, ईडी की ओर से पेश विद्वान वकील ने अभियोजन शिकायत के विभिन्न पैराग्राफों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि अपराध पीएमएलए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए काफी उपलब्ध है।

45. यह न्यायालय, प्रतिद्वंद्वी की दलील की सराहना करने के लिए, अभियोजन की शिकायत के विभिन्न पैराग्राफों को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से भरोसा किया गया है, इसे यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है ताकि मामला सामने आ सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या यह एक उपयुक्त

मामला है जहां अग्रिम जमानत दी जानी है या नहीं, पीएमएलए की धारा 45 (ii) के तहत तय किए गए पैरामीटर को पूरा किया जा रहा है या नहीं। अभियोजन शिकायत के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिए गए हैं:

2.3 केस डायरी 3941459 दिनांक के अनुसार। 24.12.2019, सुरेश प्रसाद वर्मा ने एसीई के समक्ष अपने बयान में दावा किया कि जब्त की गई नकद राशि स्वर्णरेखा परियोजना के तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम की थी और उनकी पत्नी राजकुमारी आलोक रंजन के किराए के परिसर में आती थीं। बाद में, जेल अधीक्षक, चाईबासा, प. पहली मंजिल का कमरा श्रीमती ने किराए पर लिया। देव हरि कुंज, आनंद विहार कॉलोनी, रोड नंबर 11. पीएस एमजीएम, जमशेदपुर स्थित परिसर में पुष्पा वर्मा और कमरा श्री द्वारा सुसज्जित किया गया था। एसपी वर्मा ने अलमारी सहित जहां से 2.67 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की और आलोक रंजन ने यह भी दावा किया कि जब्त की गई नकदी एसपी वर्मा की है क्योंकि वह कभी-कभी आलोक के किराए के घर पर जाता था और जरूरत पड़ने पर वर्मा के पास मौजूद चाबी वाली अलमारी का इस्तेमाल करता था। आलोक रंजन के अनुसार, आलोक की अनुपस्थिति में भी एसपी वर्मा अलमारी का इस्तेमाल करते थे और आपत्ति जताने पर एसपी वर्मा कहते थे कि उक्त अलमारी में उनका निजी सामान रखा हुआ है। आलोक ने आगे दावा किया कि वह केवल बिस्तर का इस्तेमाल करते थे और अपना सामान ट्रंक में रखते थे।

2.4 हालांकि, एस.पी. वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उक्त नकदी वीरेंद्र कुमार राम की है और आरोप लगाया कि वीरेंद्र कुमार राम स्वयं और उनकी पत्नी राजकुमारी किराए के परिसर में आलोक रंजन से मिलने आते थे और आलोक रंजन वीरेंद्र कुमार राम के चचेरे भाई हैं।

4.1.2 जांच के दौरान, सुरेश प्रसाद वर्मा ने कपिल देव यादव, पुष्पा वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा के बेटे के बीच 31.01.2022 की ईमेल के माध्यम से एक

कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की थी। उक्त कॉल रिकॉर्डिंग में, कपिल देव यादव को पुष्पा वर्मा ने कई बार इस तथ्य के साथ सामना किया था कि कपिल देव यादव ने आलोक रंजन, वीरेंद्र कुमार राम, राजकुमारी (वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी) और अन्य को घर के पहले तल पर किराए पर लेने के लिए लाया था। कपिल देव यादव ने उक्त कॉल रिकॉर्डिंग में उक्त तथ्य से इनकार नहीं किया।

7.1 पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी की कार्यवाही के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य, जो आलोक रंजन के वीरेंद्र कुमार राम के साथ संबंध और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में उनकी संलिप्तता को स्थापित करते हैं ।

दरअसल, पीएमएलए के तहत तलाशी के बाद की जांच के दौरान पता चला है कि आलोक रंजन वर्ष 2019 के दौरान वीरेंद्र कुमार राम के साथ दिल्ली जाता था। वीरेंद्र कुमार राम ने स्वयं अपने बयान दिनांक 15.04.2023 में स्वीकार किया है कि वह एक सीए मुकेश मित्तल को नकद देने के उद्देश्य से 2019 के दौरान दिल्ली जाता था, जो उसे अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ संयुक्त रूप से रखे गए बैंक खाते में प्रविष्टियां और ऐसी नकदी प्रदान करता था। वीरेंद्र कुमार राम ने टेंडर आवंटन के एवज में प्राप्त कमीशन राशि से इसे हासिल किया था। यह भी पता चला है कि आलोक रंजन और वीरेंद्र कुमार राम की रांची से दिल्ली तक की कई रेल टिकटें वीरेंद्र कुमार राम ने एक ट्रेवल एजेंट के माध्यम से बुक कराई थीं और उसका भुगतान वीरेंद्र कुमार राम ने नकद किया था।

मेसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एक ठेकेदार राजेश कुमार का बयान भी पीएमएलए की धारा 50 के तहत 07.04.2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तलाशी के दिन यानी 15.11.2019 को एसीबी जमशेदपुर द्वारा आलोक रंजन के किराए के फ्लैट (एसपी वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा के स्वामित्व वाला

घर) पर की गई, वीरेंद्र कुमार राम ने उन्हें फोन किया और आलोक रंजन के फ्लैट पर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि उनका (वीरेंद्र कुमार राम का) नकद आलोक रंजन के फ्लैट में रखा गया था, लेकिन वह फ्लैट में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि पुलिस वहां थी।

ऐसे सभी साक्ष्य, जिनकी नीचे के पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की जाएगी, यह साबित करते हैं कि एसीबी जमशेदपुर द्वारा आलोक रंजन के कब्जे से बरामद और जब्त किए गए 2.67 करोड़ रुपये केवल वीरेंद्र कुमार राम की गलत कमाई थी।

7.1.1 जांच के अन्य साक्ष्यों और निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है

खाता संख्या 11008836933 का बैंक खाता विवरण भारतीय स्टेट बैंक में वीरेंद्र कुमार राम (अभियुक्त संख्या 1) के नाम से रखे गए खाते का विश्लेषण किया गया। जब आलोक रंजन से उनके द्वारा जमा की गई ऐसी नकदी के स्रोत की व्याख्या करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने 24.02.2023 को अपने बयान में कहा कि यह नकदी उन्हें वीरेंद्र कुमार राम ने उपर्युक्त बैंक खाते में जमा करने के लिए सौंपी थी।

जब आलोक रंजन से पूछा गया कि वीरेंद्र कुमार राम द्वारा उन्हें कितनी बार और कितना नकद दिया गया है, तो उन्होंने अपने बयान दिनांक 24.02.2023 में कहा कि उन्हें वीरेंद्र कुमार राम से नकद के अलावा कुछ नहीं मिला है उपर्युक्त खाते में जमा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त नकदी से -

आलोक रंजन के पास अपराध की कमाई

7.1.9 मोबाइल फोन के विश्लेषण के दौरान वीरेंद्र कुमार राम के (आईफोन 13 प्रो मैक्स नं 9431117311) की जांच करने पर पता चला कि उनकी एक ठेकेदार श्री अनूप कुमार राय (9431301759) के साथ दिनांक 03.02.2020 को चैट हुई

थी, जिसमें अनूप कुमार राय ने वीरेंद्र कुमार राम को एक संदेश भेजा है कि "बबलू सिंह ने फॉर्च्यूनर से 3 करोड़ रुपये उड़ा लिए हैं" और साथ ही दो वाहनों का विवरण भी भेजा है, एक इनोवा जेएच 05 सीसी 1000 और दूसरा टोयोटा फॉर्च्यूनर रजिस्ट्रेशन नंबर जेएचओएससीएम 1000, जो वीरेंद्र कुमार राम को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है। इसके अलावा अनूप कुमार राय को बुलाया गया और यांत्रिक कार्यों के ठेकेदारों में से एक अनूप कुमार राय का बयान धारा 50 के तहत 07.04.2023 को दर्ज किया गया, जिसमें उनसे उक्त संदेशों के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए कहा गया और, जिसके जवाब में, उन्होंने कहा कि उन्होंने इन दो वाहनों का विवरण इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने किसी भी पिछले मुख्य अभियंता को ऐसे उच्च-स्तरीय वाहनों का उपयोग करते नहीं देखा है, इसलिए उन्होंने वीरेंद्र कुमार राम को सतर्क रहने के लिए कहा था। अनूप कुमार राय ने 05.04.2023 को अपने बयान में आगे कहा कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि वीरेंद्र कुमार राम आलोक रंजन के परिसर में पैसा रखते थे, जहां 15.11.2019 को एसीबी द्वारा तलाशी ली गई थी। उन्होंने दिनांक 07.04.2023 को अपने बयान में आगे कहा कि डब्ल्यूआरडी चांडिल कॉम्प्लेक्स के कार्यालय में चर्चा हुई थी कि बबलू (राजेश कुमार) को एसीबी जमशेदपुर द्वारा आलोक रंजन के किराए के परिसर में की गई तलाशी की तिथि यानी 15.11.2019 को तलाशी परिसर के पास पाया गया था और वह वहां से पैसों से भरे दो बैग भी ले गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि दोनों वाहन तलाशी के दिन यानी 21/02/2023 को वीरेंद्र कुमार राम के कब्जे में पाए गए थे और इन दोनों वाहनों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1-ए) के तहत फ्रीज कर दिया गया था।

7.2 अपराध से आय का सृजन वीरेंद्र कुमार राम

7.2.2 वीरेंद्र कुमार राम को 23.02.2023 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित है और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिलहाल वह रांची की होटवार जेल में बंद हैं। हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह ठेकेदारों से टेंडर आवंटन के बदले कमीशन के नाम पर रिश्त ले रहा था। उन्होंने अपने दिनांक 14.04.2023 के बयान में आगे खुलासा किया कि ठेकेदारों से ली गई कमीशन राशि कुल निविदा मूल्य का 3.2% है और उनका हिस्सा कुल निविदा मूल्य का 0.3% था जो कुछ पोस्टिंग पर 0.3% से अधिक था। हालाँकि, उसके द्वारा अर्जित अपराध की कुल आय को देखते हुए, यह माना जाता है कि कमीशन रिश्त में उसका प्रतिशत (%) अधिक रहा होगा, क्योंकि उसने स्वयं अपने दिनांक 15.04.2023 के बयान में कहा था कि उसका कमीशन 03% से 1% तक था। निविदा मूल्य का %.

7.2.3 21.02.2023 को 447/ए, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 4, अशोक नगर, रांची स्थित वीरेंद्र कुमार राम के आवासीय परिसर में तलाशी के दौरान 7,82,500 रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई। जब वीरेंद्र कुमार राम से उक्त नकदी के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने 15.04.2023 के अपने बयान में कहा कि उक्त नकदी निविदाओं के आवंटन के बदले में उन्हें प्राप्त कमीशन था।

7.2.4 दिनांक 21.02.2023 को श्री के सरकारी आवासीय परिसर में तलाशी के दौरान। वीरेंद्र कुमार राम, बंगला नंबर सीई/1. रोड नंबर 7, सीएच. एरिया ईस्ट, जुबली पार्क के पास, बिस्टुपुर, जमशेदपुर 831001, एक टोयोटा इनोवा कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH-05-CC-1000 है, जिसका रजिस्टर्ड मालिक मेसर्स

राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड (निदेशक-राजेश कुमार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) को बरामद किया गया। इसके अलावा, चौथी मंजिल, सी-334, डबरा पार्क के सामने, ब्लॉक सी, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित श्रीमती राजकुमारी के आवासीय परिसर में तलाशी के दौरान , एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार जिसका पंजीकरण संख्या JHOSCM1000 है और पंजीकृत मालिक मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बरामद किया गया। राजेश कुमार दोनों कंपनियों में निदेशक हैं। मेसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस संबंध में, वीरेंद्र कुमार राम ने 24.02.2023 को अपने बयान में कहा कि कोविड अवधि के दौरान वह उड़ानों और ट्रेनों से यात्रा करने से बच गए थे और इसलिए उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए एक चार पहिया वाहन की आवश्यकता थी। इसलिए, उन्होंने राजेश कुमार (ठेकेदारों में से एक) से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें उपर्युक्त टोयोटा फॉर्च्यूनर प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि वह ट्रेन से लौटे थे, इसलिए उक्त वाहन दिल्ली में ही रहा। इस प्रकार, फॉर्च्यूनर को जानबूझकर दिल्ली में छोड़ दिया गया था और कोविड से बचने के संबंध में कहानी को सही ठहराने के लिए बाद में सोचा गया था और ऐसे वाहन राजेश कुमार द्वारा वीरेंद्र कुमार राम को प्रदान किए गए थे क्योंकि वीरेंद्र कुमार राम ने राजेश कुमार की कंपनियों/फर्म को कई निविदाएं आवंटित की इसके अलावा, वीरेंद्र कुमार राम दो वर्षों तक उपर्युक्त टोयोटा इनोवा का उपयोग करने का कारण नहीं बता सके और कहा कि वह इस वाहन का उपयोग अपने आधिकारिक कर्तव्य के लिए कर रहे थे और उन्होंने हाल ही में राजेश कुमार की कंपनी को एक टेंडर भी आवंटित किया था।

7.3.3 आगे की जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी और पिता के बैंक खातों में बड़ी रकम प्राप्त हुई है, सबसे पहले राजकुमारी और वीरेंद्र कुमार राम के संयुक्त खाते (2577257010412) में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान लगभग 9.30 करोड़ रुपये, और फिर उनके पिता गेंदा राम के खाते से 21/12/22 से 23/01/23 तक 31-32 दिनों की अवधि में 4.5 करोड़ रुपये की राशि, ये सभी बड़ी रकम दिल्ली स्थित सीए मुकेश मित्तल के कर्मचारियों/रिश्तेदारों के खाते से स्थानांतरित की गई थी, ये खाते केवल धन को समायोजित करने और वी के राम के अवैध धन को सफेद करने के लिए खोले गए हैं।

7.4.3 जैसा कि खाता विवरण के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश धनराशि आरके नामक दो फर्मों से वीरेंद्र कुमार राम और राज कुमारी के संयुक्त बैंक खाते में जमा की गई थी। निवेश और परामर्श और आरपी निवेश और परामर्श पीएमएलए की धारा 17 के तहत राकेश कुमार केडिया और रीना पाल के निवास पर तलाशी ली गई और रीना पाल और राकेश कुमार केडिया के बयान पीएमएलए की धारा 17 के तहत 21.02.2023 को दर्ज किए गए, जिसमें बीना पाल ने अपने नाम पर किसी भी फर्म के अस्तित्व में होने या ऐसी फर्म के नाम पर किसी भी बैंक खाते के संचालन से इनकार किया। उसने बस इतना कहा कि उसका पति विजय पाल उसके सभी वित्तीय लेन-देन को संभालता है, जबकि राकेश कुमार केडिया ने 21.02.2023 के अपने बयान में कहा कि मुकेश मित्तल, उनके रिश्तेदार, उनके सभी वित्तीय लेन-देन को संभालते हैं। राकेश कुमार केडिया ने आगे कहा कि वह अपने नाम पर किसी भी फर्म के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते सीए मुकेश मित्तल के कर्मचारी विजय पाल ने 29.03.2023 को अपने बयान में आगे कहा कि उसने राकेश कुमार केडिया को अपने नाम से दो

बैंक खाते खोलने में मदद की और अपनी पत्नी रीना पाल के नाम से भी खाता खोला। उसने यह भी कहा कि उसने मुकेश मित्तल के निर्देश पर फर्म मेसर्स आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी और उसके नाम से बैंक खाता खोला था, ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल सीए मुकेश मित्तल द्वारा किया जाता था, न कि संबंधित खाताधारकों द्वारा। उसने यह भी कहा कि वह वीरेंद्र कुमार राम को जानता है क्योंकि उसके आदमी मुकेश मित्तल के कार्यालय में नकदी लाते थे।

गेंदा राम (जन्म तिथि 04.05.1941, पैन ACNPR4525L) के बैंक खाते/सी-127000628767 में प्राप्त धनराशि

7.4.10 राकेश कुमार केडिया के बैंक खातों की जांच के दौरान, गेंदा राम (वीरेंद्र कुमार राम के पिता और आरोपी आलोक रंजन के चाचा) का उपरोक्त बैंक खाता सामने आया, जिसे हमने 12.12.2022 को खोला और खाते में राकेश कुमार केडिया के बैंक खातों के रूप में उच्च मूल्य के फंड प्राप्त हुए। आगे की जांच से पता चला कि गेंदा राम के खाते में हाल ही में 30 दिनों में भारी वार प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग खसरा नंबर में 2 बीघा, 8 बिस्वा भूमि पर अचल संपत्ति खरीदने में किया गया था। 770 मिनट (1-06) 778 मिनट (1-2) सभी सुविधाओं के साथ सतबरी गांव में स्थित है जिसे ई-8 सतबरी अंसल, तहसील साकेत, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है।

7.4.12----

इस प्रकार, यह पाया गया कि कुल 4.435 करोड़ रुपये राकेश कुमार केडिया, मनीष, नेहा श्रेष्ठ और गेंदा राम के बैंक खाते (नंबर 110089477752) से गेंदा राम (127000628767) के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए) और इस राशि में से रुपये का 4.43 करोड़ रुपये की राशि। 3.39 करोड़ रुपये तीन मालिकाना बैंक खातों से वित्त पोषित किए गए थे, अर्थात् (i) श्री खाटूश्याम ट्रेडर्स

(079205500560), (ii) अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स और (082705001671) (iii) ओम ट्रेडर्स (072405001740) और एक बैंक खाते से 13 लाख रुपये ताराचंद. इन सभी तीन स्वामित्व वाले बैंक खातों का रखरखाव आईसीआईसीआई बैंक में किया जा रहा है, जो सभी एक ही मालिक, सचिन गुप्ता, पुत्र अशरफी लाल गुप्ता, के तहत काम कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि, मालिक सचिन गुप्ता ने इन तीनों में तीन अलग-अलग पैन् विवरण जमा किए हैं। अपनी स्वामित्व वाली फर्मों का और आज तक कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया (बाद में पता चला कि तारा चंद और सचिन गुप्ता एक ही व्यक्ति हैं)। रुपये का बाकी स्रोत. 91 लाख रुपये इस प्रकार हैं. मुकेश मित्तल के केनरा बैंक खाते (2577101050981) से 48.75 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। जमींदारा ट्रेडिंग के एक्सिस बैंक खाते (922020004021785) से 18:00 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, जो फील्ड सत्यापन पर गैर-मौजूद पाया गया, रु। ओयेकूल टेक्नोलॉजीज (प्रॉपर हरीश यादव) के आईसीआईसीआई बैंक खाते (425405000759) से 10 लाख रुपये, आईसीआईसीआई बैंक 425405000759 से ट्रांसफर किए गए, कृष्णा एंटरप्राइज (इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 200000747964) से 9.99 लाख रुपये और डिसेंट ट्रेडर्स (इक्विटास) से 45 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। लघु वित्त बैंक, 200001383885) ।

8. पीएमएलए की धारा 17 और 50 के तहत जांच किए गए व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण:

तलाशी और जांच के दौरान पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। इस जांच से संबंधित बयानों का सार इस प्रकार है: -

8.1 वीरेंद्र कुमार राम (अभियुक्त नंबर 1):

वीरेंद्र कुमार राम (आरोपी क्रमांक 1) ग्रामीण विभाग विशेष अंचल में मुख्य अभियंता हैं और ग्रामीण निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। हिरासत में पूछताछ के दौरान और अलग-अलग तारीखों पर न्यायिक हिरासत में पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में उन्होंने स्वीकार किया कि टेंडरों के आवंटन के बदले कमीशन लिया गया था और कुल कमीशन टेंडर मूल्य का 3.2% था और कमीशन में उनका हिस्सा कुल टेंडर राशि का 0.3% था जो 0.3% से 1% तक अलग-अलग होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि टेंडरों के आवंटन के एवज में मिले कमीशन की रकम से उन्होंने अपनी पत्नी राजकुमारी के नाम पर दिल्ली में दो अचल संपत्तियां और अपने पिता गेंदा राम के नाम पर दिल्ली में एक अचल संपत्ति अर्जित की है। उनके और उनके परिवार के पास 1,51,60,982/- रुपये के आभूषण, अपने बच्चों की विदेश में शिक्षा पर 1.25 करोड़ रुपये 19,45,100/- जो कमीशन की राशि से अर्जित किए गए थे। उसके पास ठेकेदारों/कंपनियों के नाम पर तीन वाहन भी पाए गए जो वीरेंद्र कुमार राम और उसके परिवार के उपयोग में थे, जिसके बारे में वह संतोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दे सका। वह और उसका परिवार आलीशान जीवनशैली जी रहे थे और उसने स्वीकार किया कि निविदाओं के आवंटन के बदले उसे प्राप्त कमीशन राशि से उसके द्वारा सभी खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, अपने बयान में उसने स्वीकार किया कि उसके बैंक खातों और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा नकदी, दिल्ली में 3 अचल संपत्तियां, 4 लग्जरी कारें, आभूषण, 21.02.2023 की तलाशी के दौरान उसके और उसके परिवार के सदस्यों से जब्त की गई नकदी बाहर है। निविदाओं के आवंटन के एवज में उन्हें प्राप्त कमीशन का।

8.2 गेंदा राम (अभियुक्त संख्या 4): गेंदा राम वीरेंद्र कुमार राम के पिता हैं जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं और उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष से अधिक है। गेंदा राम का बयान 21.02.2023 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेटा उनके केनरा बैंक खाते में किए गए लेनदेन के बारे में बता सकता है और वह अपने नाम पर खरीदी गई किसी भी संपत्ति से अनजान थे। हालाँकि, उनके हस्ताक्षर उन सभी चेकों पर पाए गए जिनका उपयोग ई-8, सतबरीअंसल, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।

8.3 आयुष रैपसन: आयुष रैपसन वीरेंद्र कुमार राम का बेटा है और उसका बयान 31.03.2023 और 01.04.2023 को धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि रु। पिछले 5 वित्तीय वर्षों से उनके बैंक खाते 017101527226 में 56.21 लाख नकद जमा उनके पिता द्वारा किए गए थे। उनके नाम पर एक आँडी और एक फॉर्च्यूनर भी है लेकिन वह इस आय का स्रोत नहीं बता सके। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पिता वीरेंद्र कुमार राम ने रुपये के भुगतान की व्यवस्था की है। उनके लिए 13,51,958/- रु.

8.4 मुकेश मित्तल: मुकेश मित्तल दिल्ली स्थित वीरेंद्र कुमार राम का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो गेंदा राम के बैंक खाते में फर्जी व्यावसायिक प्रविष्टियां प्रदान करने में कामयाब रहा। उनका बयान 21.02.2023 को धारा 17 के तहत और 29.03.2023 और 30.03.2023 को धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र कुमार राम ने लगभग 6 महीने पहले अपने पैतृक धन को ठिकाने लगाने के लिए उनसे संपर्क किया था, जो वास्तव में कमीशन का पैसा था। लगभग रु. दिल्ली में फार्म हाउस खरीदने के लिए अपने

पिता गेंदा राम के खाते में 5 करोड़ रु. बाद में, मुकेश मित्तल ने उक्त रुपये की व्यवस्था की। गेंदा राम के बैंक खाते में 5 करोड़ रुपये.

11. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियुक्त की भूमिका पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत

11.1 अभियुक्त नंबर 1-वीरेंद्र कुमार राम

(क) श्री वीरेंद्र कुमार राम एक सरकारी कर्मचारी हैं जो ग्रामीण विकास विशेष में मुख्य अभियंता के पद पर तैनात हैं अंचल और ग्रामीण कार्य विभाग, दोनों झारखंड सरकार के अधीन हैं।

(ख) उसने अपने पद का दुरुपयोग करके भारी मात्रा में चल-अचल संपत्ति अर्जित की। वह आवंटित प्रत्येक टेंडर कार्य के लिए कमीशन लेता था, जिससे वह सीधे तौर पर अपराध की आय अर्जित करने में शामिल हो गया।

(ग) उसने गलत तरीके से अर्जित धन या अपराध की आय अर्जित की और उसे अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की तथा उन निधियों का उपयोग उनके नाम पर चल और अचल संपत्तियां खरीदने में किया, इस प्रकार बेदाग धन को दागी के रूप में पेश किया।

(घ) वीरेंद्र कुमार राम और उनका परिवार भी एक शानदार जीवनशैली जी रहा है जो वीरेंद्र कुमार राम की वेतन आय से संभव नहीं है जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। हालाँकि, उनके पिता को पेंशन मिलती है जो किसी भी तरह से उनके परिवार की शानदार जीवनशैली का एक हिस्सा भी नहीं दे सकती है। इसलिए, वह सीधे उपयोग, कब्जे और अधिग्रहण में शामिल थे। अपराध से अर्जित आय का विवरण।

(ङ) जांच के दौरान, वीरेंद्र कुमार राम का दावा कि उनका कमीशन प्रतिशत 0.3% तय है, भ्रामक पाया गया और अपने स्वयं के बयान के बाद उन्होंने

स्वीकार किया कि उनका कमीशन निविदा मूल्य का 0.3% से 1% तक भिन्न होता था। महेंद्र गोप नामक एक ठेकेदार ने कहा कि उनके पास आमतौर पर 10% का प्रतिशत होता था, एक ठेकेदार राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने उन्हें निविदा राशि के 3% से कम कमीशन नहीं दिया था और आगे एक ठेकेदार ने कहा कि उन्हें वीरेंद्र कुमार राम को 14% कमीशन देना पड़ा था। कमीशन के अलावा, वीरेंद्र कुमार राम और उनकी पत्नी राजकुमारी ने ठेकेदारों से विभिन्न सुविधाओं और वाहनों का भी लाभ उठाया, जो कि ठेकेदारों/कंपनियों के नाम पर पंजीकृत तीन वाहनों से भी साबित हुआ। विभिन्न ठेकेदारों ने कहा है कि उन्हें अक्सर राजकुमारी और वीरेंद्र कुमार राम से वाहन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कॉल आते हैं।

(च) राजेश कुमार नामक ठेकेदार से ऋण प्राप्त करने के संबंध में वीरेंद्र कुमार राम का दावा मेगोटिया, महेंद्रगोप और अजीत सिंह को भी गुमराह करते हुए पाया गया क्योंकि इनमें से दो ठेकेदारों ने उन्हें ऋण देने से इनकार कर दिया है और यहां तक कि एक ठेकेदार महेंद्र गोप ने कहा कि वह वीरेंद्र कुमार राम के निर्देश पर कमीशन का पैसा सुरक्षित रखते थे।

(छ) इसलिए, आरोपी नंबर 1 यानी। वीरेंद्र कुमार राम ने अपने कमीशन/रिश्त राशि का दुरुपयोग करते हुए उक्त 48,94,10,877 करोड़ रुपये प्राप्त कर कम से कम 48,94,10,877/ रुपये के अधिग्रहण, कब्जे, उपयोग और छुपाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल हुए हैं। काम करते समय पोस्ट किया गया और ग्रामीण विकास (विशेष क्षेत्र) और ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड सरकार में विभिन्न पदों पर तैनात किया गया। उन्हें 38.8 करोड़ रुपये की दिल्ली स्थित अचल संपत्तियों (पैरा 9 की तालिका के क्रम संख्या 1 में उल्लिखित) और उनके 3 वाहनों (पैरा 9 की तालिका के क्रम संख्या 2 में उल्लिखित) को प्रदर्शित करने

में भी सीधे तौर पर शामिल पाया गया।) अपनी पत्नी राजकुमारी और बेटे आयुष रैपसन के नाम पर दिल्ली स्थित खातों से बेदाग संपत्ति के रूप में लगभग 1.27 करोड़ रुपये की राशि जमा की। इसके अलावा उन्होंने आईटीआर दाखिल करके और सब्जियों आदि की नकद बिक्री से आय दिखाकर अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में नकद जमा को बेदाग बताया, जो कि उनके दागी धन को बेदाग दिखाने का एक उपकरण मात्र था।

(ज) इसलिए, वीरेंद्र कुमार राम सीधे तौर पर शामिल थे, जानबूझकर एक पक्ष के रूप में हैं और वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी सभी गतिविधियों में शामिल हैं, यानी, उपयोग या अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना। पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित। इसलिए, वीरेंद्र कुमार राम पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

11.3 अभियुक्त संख्या 3 राजकुमारी (वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी)

राजकुमारी के खाता संख्या 2577101052100 के बैंक खाते के विवरण देखने पर पता चलता है कि मेसर्स आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी से 9.90,000 रुपये और मनोज कुमार सिंह से 4,00,000 रुपये जमा हैं। इसके अलावा, उनके नाम पर बैंक खाता संख्या 2577257010412 के स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि मेसर्स आरके इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी से 5,70,49,910.00 रुपये और मेसर्स आरपी इन्वेस्टमेंट से 3,59,72,230.00 रुपये जमा हैं। कंसल्टेंसी वीरेंद्र कुमार राम ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि ये क्रेडिट रेत खातों में नकदी के बदले प्राप्त प्रविष्टियों में से हैं, जिसका स्रोत वीरेंद्र कुमार राम को प्राप्त कमीशन था। इस राशि में से लगभग 9.3 करोड़ रु. अपने बैंक खाते (2577257010412)

में राजकुमारी ने साकेत, नई दिल्ली और डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली में 1.72 करोड़ रुपये (3.2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी और 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी) की अचल संपत्ति खरीदी। (क्रमशः 6.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी, जो वास्तव में वीरेंद्र कुमार राम द्वारा उत्पन्न अपराध की आय थी, जिसे बाद में उसके बैंक खाते में भेज दिया गया और बैंकिंग चैनल के माध्यम से संबंधित पहले भाग में भुगतान किया गया, जिससे बेदाग धन को दागी के रूप में पेश किया गया। वे एक शानदार जीवन शैली जीते थे जिसकी पुष्टि विभिन्न ठेकेदारों के बयानों से भी हुई है कि उपरोक्त संपत्तियों के लिए 3.28 करोड़ रुपये और 6.3 करोड़ रुपये सीधे तौर पर दिए गए थे

(बी) इसलिए, राजकुमारी सीधे तौर पर कम से कम 19.02 करोड़ रुपये की अपराध आय को कब्जे में लेने, छुपाने और उपयोग करने की प्रक्रिया में शामिल रही है और जानबूझकर इसे बेदाग दिखाने में वीरेंद्र कुमार राम की सहायता भी की है। इसलिए, आरोपी व्यक्ति राजकुमारी ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इसलिए, वह पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

11.4 आरोपी नंबर 4 गेंदा राम

(क) गेंदा ईम वीरेंद्र कुमार राम के पिता हैं और एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं, जिन्हें रुपये से कम की पेंशन मिलती है। 25,000/- प्रति माह. उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे को छतरपुर, नई दिल्ली में अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में मदद की। गेंदा राम की धुन पर 22.5 करोड़ रुपये (बैंक चैनल से 4 करोड़ रुपये और 18.5 करोड़ रुपये)। कमीशन/रिश्त की राशि से करोड़ों की नकदी, जिसे उसके बेटे वीरेंद्र कुमार राम (आरोपी नंबर 1) ने हासिल किया था। वह खाली चेक पर हस्ताक्षर करता था जो बाद में आलोक रंजन (आरोपी नंबर

4) के माध्यम से मुकेश मित्तल तक पहुंचता था, जिसका उपयोग बाद में प्रीति सिंह के बैंक खातों में धन जमा करने में किया जाता था, जिससे जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में सहायता मिलती थी। इसके अलावा, उसने बैंकिंग चैनल के माध्यम से केवल 4.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था और बाकी का भुगतान सीधे पहले पक्ष को नकद में किया गया था, जिससे वह सीधे अपराध की आय को छिपाने में एक पक्ष है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, गेरदा राम के कैनरा बैंक में रखे गए बैंक खाते के विवरण से पता चलता है कि उसमें 4.525 करोड़ रुपये जमा हैं और वीरेंद्र कुमार राम ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि यह राशि उन्हें प्राप्त कमीशन में से है।

(ग) इसलिए, गेंदा राम ने कम से कम 22.5 करोड़ रुपये की अपराध की आय को अपने पास रखने, छिपाने और उपयोग करने की प्रक्रिया या गतिविधियों में सीधे तौर पर भाग लिया है। इसलिए, आरोपी व्यक्ति गेंदा राम ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इसलिए, पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

46. अभियोजन पक्ष की शिकायत से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता राजकुमारी मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी है और याचिकाकर्ता के बैंक खाते के विवरण को देखने पर पता चलता है कि मेसर्स आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी, मनोज कुमार सिंह और मेसर्स आरके इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी से उसके बैंक खातों में भारी मात्रा में जमा राशि है। सह-आरोपी वीरेंद्र कुमार राम ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि ये जमा राशि उक्त खातों में नकदी के विरुद्ध प्राप्त प्रविष्टियों से है। जिसका स्रोत वीरेंद्र कुमार राम को प्राप्त कमीशन था। याचिकाकर्ता ने अपने नाम पर साकेत और डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली में अचल संपत्ति खरीदी है और खरीद का भुगतान सह-अभियुक्त वीरेंद्र कुमार

राम द्वारा उत्पन्न अपराध की आय से किया जाता है। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने पति द्वारा अर्जित अपराध की आय को सीधे तौर पर छिपाने की कोशिश की और कमीशन वसूल कर प्रविष्टियां प्रदान करने वाली कंपनियों से अपने बैंक खातों में प्रविष्टियां लेने की आड़ में दावा किया कि यह बेदाग है।

47. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने पति, जो सह-अभियुक्त है, को उसके नाम पर नई दिल्ली में अचल संपत्ति खरीदने में सहायता की और खरीद पर विचार का भुगतान उसके पति वीरेंद्र कुमार राम द्वारा किए गए अपराध की आय से किया गया था। . याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने पति द्वारा अर्जित अपराध की आय को सीधे तौर पर छिपाने की कोशिश की और कमीशन वसूल कर प्रविष्टियां प्रदान करने वाली कंपनियों से अपने बैंक खातों में प्रविष्टियां लेने की आड़ में दावा किया कि यह बेदाग है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री दर्शाती है कि याचिकाकर्ता के बैंक खाते के विवरण में मेसर्स आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी, मनोज कुमार सिंह और मेसर्स आरके इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी से भारी क्रेडिट हैं। सह-अभियुक्त वीरेंद्र कुमार राम ने पीएमएल अधिनियम 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया है कि ये क्रेडिट उक्त खातों में नकदी के विरुद्ध प्राप्त प्रविष्टियों से हैं, जिसका स्रोत उसे प्राप्त कमीशन था। वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध में उसकी विशिष्ट भूमिका के बारे में सामग्री है जिसका उल्लेख अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैरा-11.3 में किया गया है कि उसने अपराध की आय के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।

48. याचिकाकर्ता गेंदा राम मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार राम का पिता है और उसने जानबूझकर अपने बेटे को छतरपुर, नई दिल्ली में अपने नाम यानी गेंदा राम के नाम पर 22.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदने में मदद की, जो कमीशन/रिश्त की राशि से उसके बेटे वीरेंद्र कुमार राम (ए-1) द्वारा अर्जित की गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता

के बैंक खाते के विवरण से पता चलता है कि उसके बैंक खातों में 4.525 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा है और सह-अभियुक्त वीरेंद्र कुमार राम ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि ये जमा नकदी के बदले उक्त खातों में प्राप्त प्रविष्टियों में से हैं, जिसका स्रोत वीरेंद्र कुमार राम द्वारा प्राप्त कमीशन था। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने बेटे द्वारा अर्जित अपराध की आय को सीधे छिपाने की कोशिश की और कमीशन लेकर प्रविष्टियाँ प्रदान करने वाली कंपनियों से प्रविष्टियाँ लेने की आड़ में इसे बेदाग होने का दावा किया।

49. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने बेटे, जो सह-आरोपी है, को अपने नाम पर नई दिल्ली में 22.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां खरीदने में मदद की, जो कमीशन/रिश्वत की राशि से उसके बेटे वीरेंद्र कुमार राम द्वारा अर्जित की गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के बैंक खाते के विवरण में 4.525 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा होने का पता चलता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध में उसकी विशिष्ट भूमिका के बारे में सामग्री है, जिसका उल्लेख अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैरा-11.4 में किया गया है कि उसने अपराध की आय के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।

50. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह न्यायालय गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की याचिका पर विचार कर रहा है, जिसे सीआरपीसी की धारा 438 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में प्रदान किया जाना है। जहाँ तक गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की प्रार्थना पर विचार करने का सवाल है, कानून अच्छी तरह से स्थापित है, उक्त लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किस आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

51. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में बार-बार यह स्थापित किया है कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत शक्तियां असाधारण प्रकृति की हैं और इन्हें केवल असाधारण मामलों में ही संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और इसलिए, अग्रिम

जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है जहां अदालत का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि आवेदक को झूठे आरोप में फंसाया गया है। चूंकि अग्रिम जमानत देना कुछ हद तक अपराध की जांच के क्षेत्र में हस्तक्षेप है, इसलिए न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

52. कानून का यह भी स्थापित अर्थ है कि आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई कठोर नियम और कोई कठोर सिद्धांत नहीं है।

53. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सिद्धराम सतलीनाप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2011)1 एससीसी 694 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के कानून का सारांश प्रस्तुत किया गया है, जो गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565 में संविधान पीठ द्वारा विकसित मापदंडों पर उचित विचार-विमर्श के बाद दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"111. अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए कोई कठोर दिशा-निर्देश या सख्त फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। हमारा स्पष्ट मत है कि इस संबंध में कठोर और कठोर दिशा-निर्देश देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए भविष्य की सभी परिस्थितियों और स्थितियों की स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं की जा सकती। विधायी मंशा के अनुरूप अग्रिम जमानत देने या न देने का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। जैसा कि संविधान पीठ ने उचित रूप से कहा है। सिब्बिया मामले में निर्णय [(1980) 2 एससीसी 565: 1980 एससीसी (सीआरआई) 465] कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अपने विवेक का बुद्धिमानीपूर्ण और

सावधानीपूर्वक उपयोग करके धारा 438 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होगा, जो कि उनके लंबे प्रशिक्षण और अनुभव के कारण वे करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। किसी भी स्थिति में, यह विधायी आदेश है जिसका हम आदर और सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।

112. अग्रिम जमानत से निपटते समय निम्नलिखित कारकों और मापदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है:

- (i) गिरफ्तारी से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता और आरोपी की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए;
- (ii) आवेदक के पूर्ववृत्त में यह तथ्य शामिल है कि क्या आरोपी पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा काट चुका है;
- (iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;
- (iv) अभियुक्त द्वारा समान या अन्य अपराध दोहराने की संभावना;
- (v) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं;
- (vi) विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने के मामलों में अग्रिम जमानत देने का प्रभाव;
- (vii) अदालतों को अभियुक्तों के खिलाफ उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। अदालत को मामले में आरोपी की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की मदद से फंसाया जाता है, अदालत को और भी अधिक सावधानी और सावधानी से विचार करना चाहिए क्योंकि मामलों में अतिशयता सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है;

(viii) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए तथा अभियुक्त के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत की रोकथाम होनी चाहिए;

(ix) न्यायालय द्वारा गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका पर विचार करना;

(x) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं के दौरान, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

114. ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अग्रिम जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ये केवल उदाहरणात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि उन सभी स्थितियों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से कल्पना करना मुश्किल है जिनमें कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता है। यदि संबंधित न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग किया जाता है, तो जमानत देने या न देने के पक्ष में अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा। विधायिका ने अपने विवेक से इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सौंपी है। विधायी इरादे के अनुरूप हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहता है।"

54. सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) मामले में (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया है कि अग्रिम जमानत के आवेदनों पर फैसला करते समय न्यायालयों को निर्देशित किया जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे कारकों के आधार पर।

55. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय का न्यायिक विवेक विभिन्न प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित होगा तथा यह काफी हद तक प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम संतोष करणी एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 427 में दी गई है। त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को यहां उद्धृत किया जा रहा है:

"24. समय-परीक्षणित सिद्धांत यह है कि अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए कोई सख्त फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का न्यायिक विवेक विभिन्न प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित होगा और काफी हद तक यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए, जिसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। गिरफ्तारी से विनाशकारी और अपरिवर्तनीय सामाजिक कलंक, अपमान, अपमान, मानसिक पीड़ा और अन्य भयावह परिणाम होते हैं। इसके बावजूद, जब न्यायालय, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई भौतिक जानकारी पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी के खिलाफ संदेह की एक मात्र सुई से अधिक कुछ है, तो यह जांच को खतरे में नहीं डाल सकता है, खासकर तब जब आरोप गंभीर प्रकृति के हों।"

56. इसके अलावा, धारा 19(1), 45(1), 45(2) के प्रावधान को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जमानत का लाभ देते समय जिन शर्तों पर विचार करना आवश्यक है। सीआरपीसी की धारा 438 या 439, अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के तहत प्रदान की गई जुड़वां शर्तों के अलावा, धारा 439 या 438 के तहत जमानत देते समय जिन शर्तों या आवश्यकता का पालन किया गया है, मामला जो भी हो, उस पर विचार करना आवश्यक है।

57. विजय मदनलाल चौधरी और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ। बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) ने पी.चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की सहायता लेते हुए अग्रिम जमानत के मुद्दे से निपटते समय इस पर विचार किया है। 24 जिसमें पैराग्राफ-409 में यह देखा गया है जो इस प्रकार है:

"409. पी.चिदंबरम के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत की शक्ति का प्रयोग आर्थिक अपराधों में संयमपूर्वक किया जाना चाहिए और इस प्रकार माना जाना चाहिए:

"77. सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे और अन्य निर्णयों का उल्लेख करने और यह देखने के बाद कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 386, पैरा 19))

"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के लिए मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है और ऐसी राहत देते समय, अदालत को कारण दर्ज करना होगा इसलिए अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जब न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आवेदक को गलत तरीके से अपराध में फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम

पी.टी. मनोकरन, महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल)

आर्थिक अपराध

78. धारा 438 सीआरपीसी के तहत शक्ति एक असाधारण उपाय है, इसलिए इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए; खासकर आर्थिक अपराधों के मामलों में। आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी के हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन में, यह माना गया कि आर्थिक अपराधों में, अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

83. जांच के चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच एजेंसी को आरोपी से पूछताछ करने और उपयोगी जानकारी तथा ऐसी सामग्री एकत्र करने में बाधा आ सकती है जिसे छिपाया जा सकता है। यदि आरोपी को पता है कि वह न्यायालय के आदेश द्वारा संरक्षित है तो ऐसी पूछताछ में सफलता नहीं मिल पाएगी। विशेष रूप से आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से निश्चित रूप से प्रभावी जांच में बाधा आएगी। प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री तथा जांच के चरण को देखते हुए, हमारा मानना है कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।

84. मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में जहां "प्लेसमेंट", "लेयरिंग यानी मूल को छिपाने के लिए अन्य संस्थानों में धन का स्थानांतरण" और "पूछताछ यानी विभिन्न परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए धन का उपयोग" के कई चरण शामिल हैं, इसके लिए व्यवस्थित और विश्लेषणित जांच की आवश्यकता होती है जो बहुत फायदेमंद होगी। जैसा कि अनिल शर्मा में कहा गया है, अगर आरोपी को पता है कि वह गिरफ्तारी से पहले जमानत आदेश द्वारा संरक्षित है, तो ऐसी पूछताछ में सफलता नहीं मिलेगी। धारा 438 सीआरपीसी का पालन किया जाना चाहिएकेवल असाधारण मामलों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां आरोपित मामला तुच्छ या निराधार हो। इस मामले में अपराध की

आय को लूटने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसे विदेशी बैंकों सहित विभिन्न स्रोतों से कुछ विशिष्ट इनपुट मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनुरोध पत्र भी जारी किया गया है और विभाग को कुछ जवाब भी मिले हैं। आरोपों की प्रकृति और जांच के चरण को देखते हुए, हमारे विचार में, जांच एजेंसी को जांच की प्रक्रिया में पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हालांकि हम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट को निकालने में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमें आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारे विचार में, अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा आएगी और यह अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला नहीं है।"

(जोर दिया गया)

58.पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा) के मामले में किए गए संदर्भ से यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) में आर्थिक अपराध के मामले में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत पर विचार करने के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांत को ध्यान में रखा है, जिसे उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ-84 में भी निपटाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशिष्ट शर्त बनाई गई है, जहां इसमें "प्लेसमेंट", "लेयरिंग यानी मूल को छिपाने के लिए अन्य संस्थानों में धन स्थानांतरित करना" और "पूछताछ यानी विभिन्न अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए धन" के कई चरण शामिल हैं। संपत्ति", इसके लिए व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक जांच की आवश्यकता है जो बहुत फायदेमंद होगी।

59.माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य प्रतिनिधि में दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए। सीबीआई बनाम अनिल शर्मा, (1997) 7 एससीसी 187 द्वारा, यह मानते हुए

प्रसन्नता हुई है कि इस तरह की पूछताछ में सफलता नहीं मिलेगी यदि अभियुक्त को पता है कि वह गिरफ्तारी-पूर्व जमानत आदेश द्वारा संरक्षित है। सीआरपीसी की धारा 438 केवल असाधारण मामलों में ही लागू की जानी चाहिए, जहां कथित मामला तुच्छ या आधारहीन हो।

60. अब तत्काल मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह न्यायालय, पिछले पैराग्राफ में संदर्भित आरोपों के आधार पर, जो जांच के दौरान खोजे गए हैं, प्रथम दृष्टया यह विचार है कि विद्वान वकील की ओर से क्या तर्क दिया गया है याचिकाकर्ता ने कहा कि आय को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि आरोपों से प्रतीत होता है, आरोपी व्यक्ति वीरेंद्र कुमार राम द्वारा प्राप्त धन कमीशन के रूप में प्राप्त किया गया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग और छुपाया गया है। यह जानते हुए भी कि यह अपराध की कमाई है।

61. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि धारा 45(1) पीएमएलए के प्रावधान के अनुसार, धारा 45 पीएमएलए की जुड़वां शर्तें याचिकाकर्ताओं में से एक के रूप में याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होती हैं। अर्थात् राजकुमारी एक महिला है और दूसरा याचिकाकर्ता गेंदा राम बीमार व्यक्ति है।

62. उपरोक्त संदर्भ में पीएमएलए की धारा 45 के पहले प्रावधान पर चर्चा करना लाभदायक होगा, जो इस प्रकार है: -

"45. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। (1)

.....

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, उस पर अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर एक करोड़ रुपये से कम की राशि के मनी-लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा सकता है। यदि विशेष अदालत निर्देश दे तो जमानत पर रिहा किया जाए:"

63. उपरोक्त परंतुक के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि धारा 45 के पहले परंतुक में "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त प्रावधान का लाभ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय का विवेक, और उन्हें रिहा करना न्यायालय की ओर से अनिवार्य या अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतों को धारा 45 के पहले प्रावधान और अन्य अधिनियमों में समान प्रावधानों में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन कथित अपराधों में ऐसी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की भागीदारी की सीमा, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की प्रकृति आदि पर महत्वपूर्ण विचार किया जाएगा।

64. यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, महिलाओं, बीमार या अशक्त व्यक्तियों की श्रेणी को जमानत देने के लिए समान प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और कई अन्य विशेष अधिनियमों में भी निर्धारित किया गया है, लेकिन यदि ऐसे प्रावधान को अनिवार्य या अनिवार्य प्रकृति का माना जाता है, तो ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत सभी गंभीर अपराध महिलाओं और 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से संबंधित होंगे।

65. हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय बनाम प्रीति चंद्रा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7409/2023 में दिनांक 04.08.2023 के आदेश में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 का प्रावधान न्यायालय को जमानत देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है, जहां अभियुक्त महिला है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 के समान प्रावधानों की इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ है कि वैधानिक प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि धारा

437 की उपधारा (1) के पहले प्रावधान में निर्दिष्ट व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। (देखें प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली (2001) 4 एससीसी 280)।"

66. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशक, 2023 एससीसी ऑनलाइन 1674 के मामले में स्पष्ट रूप से माना है कि धारा 45 का पहला प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त प्रावधान का लाभ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी को न्यायालय के विवेक पर विचार करते हुए दिया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, और उन्हें रिहा करना न्यायालय की ओर से अनिवार्य या अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। त्वरित संदर्भ के लिए पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"24. अभिव्यक्ति का उपयोग "धारा 45 के पहले परंतुक में हो सकता है, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त परंतुक का लाभ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी के लिए प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। मामला, और उन्हें रिहा करना न्यायालय की ओर से अनिवार्य या अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, महिलाओं, बीमार या अशक्त श्रेणी के व्यक्तियों को जमानत देने का समान उदार प्रावधान धारा 437 सीआर में किया गया है। पी.सी. और कई अन्य विशेष अधिनियम भी, हालांकि कल्पना के किसी भी दायरे से ऐसे प्रावधान को प्रकृति में अनिवार्य या अनिवार्य नहीं माना जा सकता है, अन्यथा ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत सभी गंभीर अपराध महिलाओं और 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शामिल करते हुए किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतों को धारा 45 के पहले प्रावधान और अन्य अधिनियमों में समान प्रावधानों में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की

आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी कम उम्र के व्यक्ति और महिलाएं अधिक असुरक्षित हो सकती हैं। बेईमान तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है और ऐसे अपराध करने के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है, फिर भी, अदालतों को इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि आजकल समाज में शिक्षित और अच्छी तरह से स्थापित महिलाएं वाणिज्यिक उद्यमों और उद्यमों में खुद को संलग्न करती हैं, और जाने-अनजाने में खुद को अवैध गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं. संक्षेप में, धारा 45 पीएमएलए के पहले प्रावधान का लाभ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी को देते समय, अदालतों को अपने विवेक का उपयोग करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कथित अपराधों में ऐसी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की संलिप्तता की सीमा, प्रकृति जांच एजेंसी द्वारा एकत्र साक्ष्य आदि महत्वपूर्ण विचारणीय होंगे।

67.जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस मामले में प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता पीएमएलए की धारा 3 में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके विपरीत, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता उक्त अपराध के दोषी नहीं हैं और धारा 45 के प्रावधान में परिकल्पित विशेष लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाना चाहिए जो क्रमशः महिला और बीमार व्यक्ति हैं।

68.इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा के आधार पर न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण में कोई सार नहीं दिखता है।

69.यह न्यायालय, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपलब्ध उपरोक्त सामग्री के मद्देनजर, इस विचार पर है कि अपराध की ऐसी गंभीर प्रकृति में, जो सामग्री के आधार पर उपलब्ध है, अग्रिम जमानत देने के सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला होने

के सिद्धांत का पालन किया जाना है, यह न्यायालय इस विचार पर है कि आरोप की प्रकृति गंभीर है और इस तरह, यह अग्रिम जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।

70. तदनुसार, उपरोक्त चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय का विचार है कि तत्काल आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं और इस तरह, खारिज किए जाते हैं।

71. परिणामस्वरूप, लंबित अंतर्वर्ती आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

72. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निष्कर्ष केवल अपीलकर्ताओं को अग्रिम जमानत देने के उद्देश्य तक ही सीमित हैं और ट्रायल कोर्ट ट्रायल के दौरान इन टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश)

बीरेंद्र, ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।